

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4463
19.07.2019 को उत्तर के लिए
सूखा प्रवण क्षेत्रों में वृक्षारोपण

4463. श्री विजय बघेल:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ के सूखा प्रवण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विगत दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और उक्त अवधि के दौरान वास्तविक रूप से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के सूखा प्रवण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के लिए कोई विशेष कार्य योजना तैयार नहीं की है।

तथापि, मंत्रालय (एमओईएफ एवं सीसी) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और हरित भारत मिशन (जीआईएम) जैसी विभिन्न केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत वनीकरण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सहयोग प्रदान कर रहा है। एनएपी, जिसका कार्यान्वयन लोगों की भागीदारी के माध्यम से अवक्रमित वनों में वृक्षारोपण के लिए किया जाता है, के तहत छत्तीसगढ़ सहित देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों में समाधान के लिए अपने सात वृक्षारोपण मॉडलों में से एक मॉडल के रूप में चरागाह विकास मॉडल को भी सहयोग प्रदान किया जाता है। विगत दो वर्षों के दौरान, एनएपी के तहत छत्तीसगढ़ सहित राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

वनीकरण कार्यकलापों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) और प्रतिपूरक वनीकरण निधि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों/निधीयन स्रोतों के अंतर्गत भी कार्यान्वित किया जाता है। इसके अलावा, विभिन्न विभागों, मंत्रालयों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), सिविल सोसायटी, कॉरपोरेट आदि द्वारा भी विभिन्न केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत और बाहरी स्रोतों से सहायताप्राप्त परियोजनाओं सहित विभिन्न राज्य योजना/गैर-योजना स्कीमों के तहत बहु-क्षेत्रीय स्तर पर वन क्षेत्रों के बाहर ऐसी सभी भूमियों पर व्यापक वृक्षारोपण सहित कृषि-वानिकी/ फार्म वानिकी/ सामाजिक वानिकी जैसे वृक्षारोपण कार्यकलाप संचालित किए जा रहे हैं।

अनुबंध
'सूखा प्रवण क्षेत्रों में वृक्षारोपण' के संबंध में श्री विजय बघेल द्वारा दिनांक 19.07.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4463 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले दो वर्षों (2017-18 से 2018-19) के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) के तहत जारी की गई निधियों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(राशि: करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19
1	आंध्र प्रदेश	3.36	6.38
2	बिहार	4.23	-
3	छत्तीसगढ़	10.86	7.82
4	गुजरात	-	-
5	हरियाणा	2.71	
6	हिमाचल प्रदेश	1.73	2.92
7	जम्मू और कश्मीर	7.20	-
8	झारखंड	-	-
9	कर्नाटक	3.24	10.99
10	केरल	-	-
11	मध्य प्रदेश	8.74	7.78
12	महाराष्ट्र	6.73	15.33
13	ओडिशा	3.49	11.36
14	पंजाब	-	-
15	राजस्थान	1.40	1.95
16	तमिलनाडु	-	2.07
17	तेलंगाना	-	-
18	उत्तर प्रदेश	0.67	0.32
19	उत्तराखंड	3.36	2.58
20	पश्चिम बंगाल	-	-
	कुल (अन्य राज्य)	57.71	69.50
	पूर्वोत्तर राज्य		
21	अरुणाचल प्रदेश	0.86	-
22	असम	-	0.58
23	मणिपुर	3.20	4.38
24	मेघालय	1.65	0.74
25	मिजोरम	5.80	7.79
26	नगालैंड	5.85	6.41
27	सिक्किम	-	5.98
28	त्रिपुरा	4.94	-
	कुल (पूर्वोत्तर राज्य)	22.29	25.88
	कुल योग	80.00	95.38
